with the provisions of the Master Plan for Delhi.

(c) In view of the reply to part (a) above, the question does not arise.

Foreign Boats near Andamans

2677-B. Shrimati Savitri Nigam: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of foreign boats captured around the Andamans sea while fishing in the Indian territorial waters during the last one year?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): Altogether 10 foreign fishing vessels were captured around the Andaman and Nicobar Islands in the Indian Territorial Waters during the last one year.

11.20 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Seizure of Indian Consulate in Sumatra and Property of Indians in Java and the Confiscation of Property of Indians in Indonesia

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इसके बारे में नोटिस हमने 16 तारीख को दिया था, कल इसी के सम्बन्ध में एक उत्तर राज्य सभा में दे दिया गया है। इस प्रकार के अनेकों नोटिस होते हैं जिनका उत्तर पहले वहां दे दिया जाता है। बहुत से महत्वपूर्ण वक्तव्य भी होते हैं जो कि पहले वहां दे दिये जाते हैं और बाद में यहां दिये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरफ आप ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी तहकीकात करूंगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह अनुचित है।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"सुमात्रा में भारतीय वाणिज्य दूतावास और जावा में भारतीयों की सम्पत्ति पर कब्जा करने तथा इंडोनेशिया में भारतीयों की सम्पत्ति के जब्त किये जाने के समाचार"।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : भारत सरकार को यह जानकर बड़ा दुख हुआ है कि नार्थ सुमात्रा यूथ फ्रन्ट ने 13 सितम्बर, 1965 को सबेरे मैदान में भारतीय कौंसलावास के सामने भारी प्रदर्शन किया। कौंसल के विरोध के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने कौंसलावास की इमारत से भारत का राष्ट्रीय ध्वज नीचे उतार दिया और उसकी जगह इण्डोनेशिया का राष्ट्रीय झण्डा लगा दिया। इन प्रदर्शनकारियों ने कौंसलावास से भारत का राष्ट्र चिह्न तथा नाम पट्टिका भी हटा दी, और उसे ले गये; व किताबों की दो आलमारियों को भी ले गये जिनमें लाइब्रेरी की किताबें थीं। ये लोग भारत के राष्ट्रपति का चित्र भी ले जाना चाहते थे परन्तु भारत के कौंसल ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया।

हमारे कौंसल ने पहले ही उत्तरी सुमात्रा के गवर्नर को लिखा था कि वे

[श्री दिनेश सिंह]

कोंसलावास के कर्मचारियों और संपत्ति की सभी तरह से रक्षा करने की व्यवस्था करें। फिर भी, ड्यूटी पर जो पुलिस थी उसने प्रदर्शनकारियों को रोका नहीं। यह निस्संदेह बिल्कुल स्पष्ट है कि इण्डोनेशिया की सरकार इण्डोनेशिया की धरती पर स्थित विदेशी मिशनों की समुचित रक्षा करने के अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा नहीं कर पाई है। हमारे कोंसल ने रिपोर्ट दी है कि वह उत्तरी सुमात्रा के गवर्नर से मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं। जकार्ता में हमारे राजदूत ने इण्डोनेशिया के विदेश कार्यालय से विरोध प्रकट किया है।

जकार्ता में 18 सितम्बर को सभी भारतीयों की दुकानों और मकानों पर पुलिस ने ऐसे पर्चे चिपका दिये जिन पर लिखा है—"इण्डोनेशिया सरकार की रक्षा में"! पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिये की गई है जिससे संपत्ति की रक्षा की जा सके और कोई दुर्घटना न होने पाए। भारतीय व्यापारियों से यह भी कहा गया है कि संपत्ति यद्यपि उन्हीं की है, परन्तु वे अपनी दुकानों और मकानों को बेच नहीं सकते और न ही उन्हें हस्तांतरित कर सकते हैं। हमारे राजदूत इस प्रश्न पर भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत कर रहे हैं।

पश्चिम जावा के गवर्नर ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार सुरक्षा कारणों से 11 सितम्बर से भारतीय संपत्ति सुरक्षात्मक अधिकार में ले ली गई है। इस प्रांत के पुलिस-अध्यक्ष को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह जब चाहे इस संपत्ति को इस आदेश की व्यवस्थाओं से मुक्त कर दे।

जकार्ता के गांधी मेमोरियल स्कूल को, जो भारतीयों का है और वे ही उसकी प्रबन्ध-व्यवस्था भी करते हैं तथा जिसे इन्डोनेशियन नेशनल फ्रन्ट ने ले लिया था, अब खुलने की इजाजत दे दी गई है। मैदान का खालसा स्कूल सरकारी प्राधिकारियों ने अपने हाथ में ले लिया है।

श्री बागड़ी (हिसार) : इस जवाब पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने ऐसा एक विचित्र जवाब दिया है जो कि बुद्धि की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, जो कि जंचता नहीं है। प्रदर्शनकारी लाइब्रेरी तो ले गये लेकिन राष्ट्रपति की तस्वीर ले जाने लगे तब रोक दिया गया। किताबें जब ले जा रहे थे तब उनको क्यों नहीं रोक दिया था ....

अध्यक्ष महोदय : यह क्या व्यवस्था का प्रश्न हुआ? कौन से रूल की उल्लंघना हुई है जो मैं जवाब दे सकूं। यह तो आप उन से पूछ रहे हैं। व्यवस्था का प्रश्न तो वह होता है जिसका मैंने फैसला देना होता है, मिनिस्टर को फैसला नहीं देना होता है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : इंडोनेशिया सरकार अपने कर्तव्य को निभाने में असफल हो रही है क्या यह सही है? क्या यह भी सही है कि वह इस तरह के काम करने के लिए लोगों को भड़का रही है और लोगों से कह रही है कि ऐसा वे करें? क्या यह भी सही है कि जो महिलायें भारत लौट रही थीं उनको वहां उन्होंने गोली मारने की धमकी दी थी?

श्री दिनेश सिंह : वक्तव्य में मैंने स्पष्ट कह दिया है कि इंडोनेशिया की सरकार की जो जिम्मेदारी है वह उसको अच्छी तरह से नहीं निभा पा रही है। इन सब बातों में कितना सरकार का हाथ है, कितना नहीं है यह हमारे लिये कहना बड़ा मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय : औरतों के बारे में जो पूछा है?

श्री दिनेश सिंह: कुछ घटनायें वहां पर सुना जाता है कि हुई थीं : उसका पूरा ब्यौरा हमारे पास नहीं आया है ।

Shri Hem Barua (Gauhati): In view of the fact that Indonesia has openly and actively supported Pakistan's aggression on us, and these acts of violence or vandalism of Indonesian crowds are the results of this support, may I know (a) whether our Government have succeeded in projecting India's case adequately for consumption by the Indonesian public, (b) whether our Government propose any high-level dialouge with the Indonesian Government. . .

An Hon. Member: Dialogue?

Shri Hem Barua: That is good English, I suppose.

Mr. Speaker: I have to accept whatever the learned professor says.

Shri Hem Barua: . . .so as to improve relations between the two countries, and (c) whether the word 'supervision' in the Indonesian vocabulary means anything up to the confiscation of our property?

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): What about part (d) of the question?

Shri Dinesh Singh: We are not proposing any special dialogue. So far, it has been a monologue on the part of our Ambassador. So far as part (c) of the question is concerned, we have been informed that this property has been taken under the protection of Government only to afford protection against hooliganism, and, there is no proposal at this stage for any nationalisation or taking over.

Shri Hem Barua: What about part (a)?

Shri P. Venkatasubbaiah (Adoni): May I know whether this is a calculated and concerted mischievous action of the Government of Indonesia with the encouragement of Peking and Pindi to provoke us into the action of severing our diplomatic relations with that Government? If so, will Government succumb to these machinations?

Shri Dinesh Singh: The House and the whole world are aware that we have not been pushed into any action because of what Pindi or Peking have done.

श्री बशपाल सिंह (कैराना): क्या सरकार यह बतला सकती है कि नेशनलाइजेशन से हिन्दुस्तान के दुकानदारों और व्यापारियों को कुल कितना नुकसान हुआ है । और जब पाकिस्तान से भी आगे-आगे इंडोनेशिया चल रहा है और पाकिस्तान से ज्यादा वह हिन्दुस्तान की मुखालफित कर रहा है तब क्या सरकार ने सोचा है कि उस के डिप्लोमैटिक रिलेशन्स को खत्म किया जाये और जो सिस्टम चल रहा है उस को रोका जाये ।

Mr. Speaker: Shri P. R. Chakraverti.

Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad): Is it a fact that the Press *Attache* to the Indian Embassy has been threatened with violence? If so, what action has been taken by Government to save him?

Shri Dinesh Singh: The Indonesian Government have informed us that they are taking adequate precautions.

श्री डांगी : क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि हिन्देशिया के एक राजदूत ने अपने एक बयान के दौरान इस बात का इंकशाफ किया है कि हिंदेशिया सरकार ने भारत के खिलाफ जो नीति अपनाई है हिंदेशिया की जनता उसके पीछे नहीं है । अगर सरकार की नोटिस में यह बात आई है तो सरकार इसके बारे में क्या कर रही है ।

श्री दिनेश सिंह: हमने तो खुद इस सदन में इस बात को अर्ज किया था कि हमारी सरकार की जो नीति इस वक्त है उस से हम यह नहीं समझते हैं कि इंडोनेशिया की जनता उन के साथ है । हमारी जनता और इंडोनेशिया

[श्री दिनेश सिंह]

की जनता के बीच में मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बने हैं ।

श्री उदिया (शहडोल): जो कुछ जावा और सुमात्रा में हुआ है क्या वैसे ही हिन्दुस्तानियों के साथ बाली द्वीप में भी हुआ है ।

Mr. Speaker: If he has the information, he might give it; otherwise not. It is not actually relevant here.

Shri Dinesh Singh: We are not aware of any loss.

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): हिंदेशिया के शत्रु व्यवहार को अब सरकार ने पूरी तरह से देख लिया है । तो क्या उस से सरकार ने नतीजा निकाला कि बांडुंग सिद्धान्त और अफ्रेशियाई देशों के बीच वर्गीकरण किया जाये अर्थात् हिन्दुस्तान के हित और दुनिया की भलाई की दृष्टि से अफ्रेशिया में कौन से भले और मित्र देश हैं और कौन से ऐसे देश हैं जिन के प्रति अगर शत्रुता नहीं तो कम से कम उपेक्षा दिखाई जाये । अगर ऐसा किया है तो वे कौन कौन से देश हैं ?

श्री दिनेश सिंह : हमारा तो प्रयत्न रहता है कि सभी देशों से मित्रता पूर्ण सम्बन्ध रहें। बीच बीच में कुछ देशों की सरकारें दिक्कतें पैदा करती है । जब वह दिक्कतें हमारे सामने आती हैं तो उन का हमें मुकाबला करना पड़ता है । लेकिन हम ने कोई कोशिश नहीं की है कि और देशों में किसी दूसरे देश के प्रति कोई बुरा प्रचार फैलायें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरा वर्गीकरण का प्रश्न था अध्यक्ष महोदय ।

Mr. Speaker: Whether any classification has been made of countries as friendly, not too friendly and so on?

Shri Dinesh Singh: I think the House is aware of that also from the actions of these countries.

श्री किशन पटनायक (सम्भलपुर): रूस, अमरीका, अफ्रेशियाई और निरपेक्ष, इन चार प्रकार की विदेशी शक्तियों के साथ हम मित्रता की कोशिशकर रहे है । लेकिन अभी तक अफ्रेशियाई और निरपेक्ष देशों के ऊपर हम जितना समय और मेहनत खर्च कर चुके हैं उस के अनुपात में, जब कि पाक और हिन्द की लड़ाई चल रही है, हमें फायदा नहीं पहुंचा है । इसको ध्यान में रखते हुए क्या भविष्य में हम अपनी विदेश नीति में कोई तब्दीली करेंगे ।

श्री दिनेश सिंह : एशिया में रहते हुए एशियाई देशोंके साथ हम मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाने की कोशिश न करें यह हमारे लिये एक गलत नीति होगी, और यही बात अफ्रीका के सम्बन्ध में आती है । हमारे उन के जो सम्बन्ध हैं वह स्वाभाविक सम्बन्ध हैं । लेकिन साथ साथ हम और देशों से भी मित्रता पूर्ण सम्बन्ध बनाने की कोशिश करते हैं । मैं नहीं समझता कि नीति में किसी परिवर्तन का सवाल उठता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : भले ही पिटते चले जाओ लेकिन नीति में परिवर्तन नहीं होगा ।

Mr. Speaker: The Prime Minister would be making his statement at

15.30 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

EXPLANATORY NOTE ON THE SCHEME OF WAR RISKS INSURANCE OF MARINE HULLS

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): Sir, I beg to lay on the Table a copy of an Explanatory Note on the Scheme of War Risks Insurance of Marine Hulls together with the outline of the Scheme. [*Placed in Library. See* No. LT-4918/65].